(a) whether Government propose to set up some sugar mills in the country both in the private and the public sectors on modern lines; and

(b) if so, the details thereof, and the investment proposed to be made therein?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) and (b) The Central Government does not propose specific areas to set up new sugar factories in any part of the country. The applications for grant of LOI/IL for establishment of new sugar mills are received through the Department of Industrial Development, which are then considered by the Department of Food as per licensing guidelines. However, during the VIIth Five Year Plan (as on 15-4-90), 85 Letters of Intent comprising 66 cooperative, 1 public and 18 private sector have been issued for establishment of new sugar factories.

The total financial requirement for the above projects would be approximately Rs. 2,262 crores.

Ban on new employment in the Central Warehousing Corporation

*153. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is a ban on new employment in the Central Warehousing Corporation; if so, since when; and

(b) whether this has resulted in the various godowns of the Corporation being under staffed with adverse effect on the work of the godowns?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खाद्यान्न उत्पादन संबंधी विशेष कार्यक्रम

***154. श्री राम जेटमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अगले वर्ष से "खाद्यान्न उत्पादन संबंधी विशेष कार्यक्रम" प्रारंभ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में अगले वर्ष हेतु कृषि उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा "खाद्यान्न उत्पादन संबंधी विशेष कार्यक्रम" के अधीन किसानों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु प्रमाणित बीजों, उर्वरकों, बिजली आदि की कितनी-कितनी मात्रा निर्धारित की गयी है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां। देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिये खरीफ 1988 से विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 1990–91 के दौरान भी क्रियान्वित किया जायेगा ।

(ख) 1990–91 के लिये 176.5 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) केवल विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिये प्रमाणीकृत बीजों, उर्वरकों, बिजली आदि का अलग से कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, अधिक उत्पादन देने वाली विशिष्ट किस्मों के बीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये गये हैं, उर्वरकों और कृमिनाशी दवाओं की बिक्री के लिये अतिरिक्त खुदरा केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है । समेकित कृमि प्रबंध पर

विशेष बल दिया गया है। कृषि क्षेत्र को बिजली की सप्लाई के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बिजली की समग्र उपलब्धि के अनुरूप विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिये अधिक से अधिक बिजली की सप्लाई करने के लिये राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि के क्षेत्र में चीन के साथ चर्चा

*155. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
डा० ग्रेलामनचिली शिवाजी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की चीन-यात्रा के दौरान भारत-चीन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये कृषि के क्षेत्र में कुछ समझौते करने के संबंध में कोई चर्चा की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हरित क्रांति भारत की तुलना में चीन में अधिक सफल हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वैसी प्रविधियां देश में अपनाने का विचार रखती है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (घ) उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने 23 से 27 अप्रैल, 1990 को बीजिंग में हुये एशिया और प्रशांत के 20 वें खाद्य एवं कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये और चीनी प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिये 23 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1990 तक चीन का दौरा किया।

चीन और भारत दोनों में हरित क्रांति आई है, जिससे कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। तथापि किसी भी देश में कृषि उत्पादन की पद्धति इसकी कृषि जलवायु की स्थिति और सामाजिक-आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है। चीन जनवादी गणतंत्र ने संकर चावल उत्पादन, कार्बनिक पदार्थों का पुनः इस्तेमाल करने की तकनीक, प्लास्टिी कल्चर तकनीक, समेकित मत्स्य-धान खेती, अल्प अश्व शक्ति कृषि मशीनरी, धान की भूसी का गैसीकरण, सूअर, भेड़ और बकरियों आदि की उच्च बहुफलदायक नस्ल और ताजा जल और खारा जल जलकृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रगति की है। जिसमें भारत ने भावी सहयोग के लिये रुचि दिखलाई है। विचार-विमर्श के दौरान चीन जनवादी गणतंत्र ने भारत से कपास उत्पादन, गन्ने की अधिक उपज देने वाली और अधिक चीनी का उत्पादन देने वाली किस्मों, पनधारा के आधार पर बारानी और वर्षा सिंचित फार्म प्रौद्योगिकी सिंचाई परियोजनाओं का कमान क्षेत्र प्रबंधन, भैंस और भस के भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ में दूध के उत्पादन और परिसंस्करण की प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। इन आधारों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से चीन और भारत को अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में परस्पर लाभ मिलेगा।

Functioning of Sambalpur Railway Division

*156. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had recently announced that Sambalpur Railway Division would start functioning immediately; and

(b) if so, the progress made in this regard so far?